International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक शासन के आयामों का अन्वेषण: संरचनाएं, अभिनेता और प्रक्रियाएं

डॉक्टर नमिता कुमारी

असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एस.पी.एम. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Date of Submission: 27-03-2024 Date of Acceptance: 06-04-2024

सार

यह शोध लेख संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रशासन की बहुमुखी प्रकृति की पड़ताल करता है। इसकी संरचनाओं, अभिनेताओं, प्रक्रियाओं, चुनौतियों और नवाचारों पर प्रकाश डालता है। यह शैक्षिक प्रशासन और इसके प्रमुख घटकों को परिभाषित करने से शुरू होता है, जिसमें नीति निर्माण, जवाबदेही, संसाधन आवंटन और हितधारक जुड़ाव शामिल हैं। यह लेख शैक्षिक प्रशासन के ऐतिहासिक विकास का पता लगाता है, ऐतिहासिक विधानों और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

जटिल शासन संरचनाओं की जांच करते हुए, यह लेख संघीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों की भूमिकाओं के साथ-साथ विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिनेताओं के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करता है। इसके बाद यह नीति निर्माण, वित्त पोषण तंत्र, जवाबदेही उपायों और निर्णय लेने में हितधारक की भागीदारी की जटिल प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

लेख कई चुनौतियों और विवादों की पहचान करता है, जैसे समानता और पहुँच के मुद्दे, मानकीकृत परीक्षण और जवाबदेही के आसपास बहस, निजीकरण और स्कूल की पसंद का उदय और राजनीतिक ध्रुवीकरण। यह आशाजनक नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं की भी खोज करता है, जिसमें सहयोगात्मक शासन दृष्टिकोण, सामुदायिक स्कूलों और भारित छात्र वित्त पोषण जैसे सफल शासन मॉडल और डेटा-संचालित निर्णय लेने, इक्विटी और सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत शिक्षा और प्रौद्योगिकी एकीकरण जैसे उभरते रुझान शामिल हैं।

1. परिचय

शिक्षा प्रबंधन में शिक्षा क्षेत्र के प्रबंधन, विनियमन और निर्णय लेने में शामिल संरचनाएं, प्रक्रियाएं और तत्व शामिल हैं। इसमें शिक्षा वितरण में गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाना और लागू करना, संसाधनों का वितरण करना और शैक्षणिक संस्थानों की देखरेख करना शामिल है। शिक्षा प्रबंधन में निर्णय लेने और संसाधन आवंटन के लिए नियमित और गैर-नियमित तरीकों का संयोजन शामिल है। यह शिक्षा प्रणालियों के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों तक फैला हुआ है, जैसे कि संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर, सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक भागीदार और गैर सरकारी संगठन। न्याय, उत्कृष्टता और सामाजिक जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षा प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए नीति निर्माण, जवाबदेही, संसाधन आवंटन, हितधारक भागीदारी और निर्णय लेने की संरचनाओं जैसे शिक्षा प्रबंधन के आवश्यक तत्वों को समझना महत्वपूर्ण है। सामंजस्य. शिक्षा प्रबंधन का अध्ययन राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन,

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों से विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर आधारित है। ये सिद्धांत शिक्षा प्रबंधन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सहायता प्रदान करते हैं। प्रमुख दृष्टिकोणों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था, संस्थागत सिद्धांत, नया सार्वजनिक प्रबंधन, नागरिकता सिद्धांत और नेटवर्क प्रबंधन शामिल हैं। शिक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण अवधारणाओं में स्वदेशीकरण, जवाबदेही, न्याय और सार्वजनिक भागीदारी शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्रबंधन पर अनुसंधान ने नीतियों को आकार देने, चर्चाओं में योगदान देने और सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. शैक्षिक प्रशासन का इतिहास

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रशासन की जड़ें औपनिवेशिक काल तक जाती हैं, जब शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा निभाई जाती थी (कैसटल, 1983)। इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा आकार लेनी शुरू हुई, जिसमें 1635 में बोस्टन में पहले सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना हुई (मॉनडेल और पैटन, 2001)।

19वीं सदी के प्रारंभ में, होरेस मैन और हेनरी बार्नार्ड जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने "सामान्य विद्यालयों" की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें सभी बच्चों के लिए मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा का प्रावधान था (मॉनडेल और पैटन, 2001)। इस अवधि में राज्य शिक्षा बोर्डों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे शिक्षा के प्रशासन संरचनाओं को और आकार मिला (कैसटल, 1983)।

बीसवीं सदी के मध्य काल में कई महत्वपूर्ण कानूनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया। ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड के 1954 के फैसले में सार्वजनिक विद्यालयों में नस्लीय पृथकतावाद को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिससे शैक्षिक संस्थानों के विसंगठन और शैक्षिक समानता के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ (पैटरसन, 2001)।

1965 का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (ईएसईए), जो राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन के "गरीबी पर युद्ध" का एक प्रमुख अंग था, ने शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय शासन की भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि की (मैकडोनेल, 2005)। इस कानून ने वंचित छात्रों के समर्थन के लिए केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया और जवाबदेही उपायों की शुरुआत की, जिससे शैक्षिक नीति निर्माण में अधिक केंद्रीकरण की ओर बढ़ना शुरू हुआ (जेनिंग्स, 2015)।

1975 का शिक्षा सभी विकलांग बच्चों अधिनियम (बाद में व्यक्तिगत विकलांगता शिक्षा अधिनियम या आईडीईए के रूप में जाना जाने लगा) ने विकलांग छात्रों के लिए मुफ्त और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जिससे शैक्षिक प्रशासन और नागरिक अधिकारों में केंद्र सरकार की भूमिका और अधिक बढ़ गई (यैल, 2016) ।

2001 का नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड अधिनियम (एनसीएलबी), एक द्विदलीय शिक्षा सुधार पहल, में छात्र उपलब्धि से केंद्रीय वित्त पोषण जोड़ते हुए एक व्यापक मानकीकृत परीक्षा और जवाबदेही प्रणाली शुरू की गई (डी और जेकब, 2011)। यह कानून शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय प्रभाव के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है, जिससे राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर बहस छिड़ गई (मैकगिन, 2016)।

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रशासन को इतिहास के दौरान विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक बलों और आंदोलनों द्वारा आकार दिया गया है। 1950 और 1960 के दशकों के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्लीय समानता और विसंगठन के

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

मुद्दों को सामने लाया, जिससे शिक्षा के प्रशासन में बदलाव लाने वाले महत्वपूर्ण कानूनी फैसले और विधायी कार्रवाइयां हुईं (पैटरसन, 2001)।

20वीं सदी के अंतिम चरण में उदारवादी नीतियों और बाजार-आधारित सुधारों के उदय ने शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित किया, जिसमें स्कूल चुनाव, चार्टर स्कूल और मानकीकृत परीक्षाओं पर आधारित जवाबदेही उपायों जैसी पहलों को बढ़ावा मिला (लुबिएंस्की, 2005)।

हाल के दशकों में, प्री-किंडरगार्टन और प्रारंभिक अधिगम कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन संरचनाओं को विस्तारित और सुधारने की आवश्यकता को लेकर प्रारंभिक बाल शिक्षा के महत्व को पहचानने पर जोर दिया गया है (बार्नेट और मास्से, 2007)। इसी तरह, कॉलेज और कैरियर की तैयारी पर बल देने ने पाठ्यक्रम के मानकों, मूल्यांकन पद्धतियों और शैक्षिक प्रशासन प्रणालियों में जवाबदेही उपायों में बदलाव लाया है (कॉनले, 2014)।

जैसे-जैसे समाज की जरूरतें और प्राथमिकताएं बदलती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा के प्रशासन में भी बदलाव आता रहा है, जो शैक्षिक नीतियों, सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों और शिक्षा की प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बदलते परिदृश्य के बीच गतिशील अंतर्क्रिया को दर्शाता है।

3. शिक्षा प्रबंधन में संरचनाएँ

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जटिल और बहु-स्तरीय शिक्षा प्रबंधन प्रणाली है। कई देशों में पाए जाने वाले केंद्रीकृत शिक्षा मंत्रालय के विपरीत, यूएसए फेडरल, राज्य, और स्थानीय स्तरों पर अधिकार सौंपता है।

A. फेडरल स्तर: राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करना

फेडरल स्तर पर, यू.एस. शिक्षा विभाग (DOE) राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसका स्कूलों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, DOE फंडिंग प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, अनुदान कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है, और राज्यों और स्कूल जिलों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विभाग राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों और ढांचों के विकास का नेतृत्व करता है, जो पूरे देश में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रथाओं को प्रभावित करता है।

B. राज्य: संचालन का कार्य

राज्य शिक्षा एजेंसियां (SEAs) और शिक्षा बोर्ड (BOEs) प्रत्येक राज्य के भीतर केंद्रीय अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। SEAs, अक्सर राज्य-नियुक्त सुपरिन्टेंडेंट्स द्वारा देखरेख की जाती हैं, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन निर्माण, और शिक्षक प्रमाणन सहित विविध कार्यों का प्रबंधन करती हैं। BOEs, अक्सर जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यव्यापी शैक्षणिक मानकों की स्थापना करते हैं और जिलों को राज्य शिक्षा फंड के आवंटन की देखरेख करते हैं।

राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रण की डिग्री काफी भिन्न होती है। कुछ राज्यों ने अधिक केंद्रीकृत मॉडल अपनाए हैं, जो पाठ्यक्रम और मूल्यांकनों को निर्धारित करते हैं, जबकि अन्य स्थानीय जिलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। यह भिन्नता शिक्षा में फेडरलिज्म के बारे में चल रही बहसों को दर्शाती है, जिसमें कुछ शैक्षणिक न्याय सुनिश्चित करने में एक मजबूत राष्ट्रीय भूमिका के लिए वकालत करते हैं, जबकि अन्य पाठ्यक्रम और निर्णय लेने पर स्थानीय नियंत्रण का समर्थन करते हैं।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

C. स्थानीय स्तर: जहां शिक्षा जड़ें जमाती है

शैक्षणिक प्रणाली का दिल स्थानीय स्तर पर होता है, जहां व्यक्तिगत स्कूल जिलों और उनके शासन बोर्डों के पास महत्वपूर्ण शक्ति होती है। स्कूल बोर्ड्स, आमतौर पर समुदाय द्वारा चुने जाते हैं, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, भर्ती प्रथाओं, बजटीय निर्णयों, और स्कूल संचालन पर काफी अधिकार रखते हैं। वे समुदाय और स्कूलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, शैक्षणिक अनुभवों को आकार देने में सार्वजनिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

जिलों के भीतर स्कूल शासन में स्कूल बोर्ड, सुपरिन्टेंडेंट (जो दैनिक संचालन की देखरेख करते हैं), और प्रिंसिपल जो व्यक्तिगत स्कूलों का नेतृत्व करते हैं, के बीच एक जटिल अंतःक्रिया शामिल है। इसके अलावा, अभिभावक और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसमें अभिभावक-शिक्षक संघों (PTAs) और स्कूल सलाहकार परिषदों जैसे तंत्र भागीदारों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं।

4. शैक्षिक शासन के कर्ता

A. सरकारी तंत्र

केंद्रीय स्तर पर शिक्षा कानून पारित करते हैं, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में यू.एस. शिक्षा विभाग इन कानूनों को विनियमों और वित्त आवंटन के माध्यम से क्रियान्वित योग्य नीतियों में परिवर्तित करता है। राज्य शिक्षा एजेंसियां (SEAs), जो अक्सर राज्य महानिदेशकों के प्रभारी होती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पाठ्यक्रम मानक विकसित करते हैं, मानकीकृत मूल्यांकन तैयार करते हैं, और शिक्षक प्रमाणन पर नज़र रखते हैं। स्थानीय स्कूल जिले, जिनकी अगुवाई निर्वाचित स्कूल बोर्ड करते हैं, काफी शक्ति रखते हैं। स्कूल बोर्ड पाठ्यक्रम कार्यान्वयन निर्धारित करते हैं, शिक्षकों और प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, बजट प्रबंधित करते हैं, और दैनिक संचालन पर नज़र रखते हैं।

B. दबाव डालने वाले: गैर-सरकारी कर्ता

हितों के समूह और वकालत संगठन: गैर-सरकारी कर्ता , जैसे शिक्षक संघ, व्यवसाय लॉबी और अभिभावक वकालत समूह, शिक्षा नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वे विधायकों पर दबाव डालते हैं, राज्य बोर्डों को प्रभावित करते हैं, और मानकीकृत परीक्षण, स्कूल चुनाव और शिक्षक वेतन जैसे मुद्दों पर जनमत गढ़ते हैं। पेशेवर संघ, जैसे नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन (NEA), शिक्षकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे शिक्षक कार्य स्थितियों, पाठ्यक्रम मानकों और व्यावसायिक विकास अवसरों से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के लिए वकालत करते हैं।

C. स्वयं संस्थान: शैक्षिक संस्थान
विद्यालय, विशेष रूप से उच्च विद्यालय जिनके पास पाठ्यक्रम प्रस्तावों में स्वायत्तता होती है, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित ढाँचे के भीतर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भावी शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोध विश्वविद्यालय शिक्षा नीति को शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और शैक्षिक नेतृत्व पर ज्ञान उत्पन्न करके और प्रभावित करते हैं।

D. आवाज़ रखने वाले हितधारक: समुदाय सदस्य

अभिभावक और छात्र: अभिभावक बढ़ते हुए मुखर हितधारक हैं, जो स्कूल बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए वकालत करते हैं, और स्कूल चुनाव के निर्णयों के माध्यम से पाठ्यक्रम को प्रभावित कर छात्र स्वयं, छात्र परिषदों या विरोध

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

आंदोलनों के माध्यम से, मुद्दों को उजागर कर सकते हैं और स्कूल नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।

समुदाय के सदस्य: समुदाय के सदस्य, जिनमें धार्मिक संगठन, स्थानीय व्यवसाय और सांस्कृतिक संस्थान शामिल हैं, स्कूलों के साथ साझेदारी कर सकते हैं और संसाधन, स्वयंसेवक अवसर और समृद्धि कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। उनकी भागीदारी शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध बना सकती है और समुदाय में स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दे सकती है।

5. शैक्षिक शासन की प्रक्रियाएँ

अमेरिका में शैक्षिक शासन का जटिल जाल न केवल अपने कर्ताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, बल्कि उन जटिल प्रक्रियाओं द्वारा भी जिनके माध्यम से नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है।

A. नीति निर्माण और कार्यान्वयन

केंद्रीय और राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रियाएँ अमेरिका में शैक्षिक नीतियाँ केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं। राज्य स्तर पर, राज्य विधानसभाएं अपने संबंधित राज्य संविधानों और स्थानीय परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा कानूनों और नीतियों को गढ़ने और पारित करने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। नियामक एजेंसियाँ शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपने विभिन्न कार्यालयों और एजेंसियों के माध्यम से, अमेरिकी शिक्षा विभाग केंद्रीय शिक्षा कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए विनियम, दिशा-निर्देश और नियम विकसित और जारी करता है। इसी तरह, राज्य शिक्षा एजेंसियाँ और बोर्ड राज्य शिक्षा कानूनों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियम और नियम बनाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

B. वित्तपोषण और संसाधन आवंटन

केंद्रीय और राज्य वित्तपोषण तंत्र अमेरिका में शिक्षा के लिए वित्तपोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के बीच एक साझा ज़िम्मेदारी है। राज्य सरकारें विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनमें आय कर, बिक्री कर और संपत्ति कर शामिल हैं। राज्य वित्तपोषण सूत्र स्थानीय स्कूल जिलों को संसाधनों के आवंटन निर्धारित करते हैं, जो अक्सर छात्र नामांकन, जनसांख्यिकीय और शैक्षिक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं। स्थानीय बजटन और संसाधन वितरण स्थानीय स्तर पर, स्कूल जिले और शिक्षा बोर्ड अपने स्वयं के बजट विकसित और प्रबंधित करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जिनमें राज्य और केंद्रीय स्रोतों से धन के साथ-साथ स्थानीय कर राजस्व भी शामिल होता है।

C. शैक्षिक जवाबदेही और मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक शासन जवाबदेही प्रणालियों में मानकीकृत परीक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इन आकलनों का उपयोग छात्र उपलब्धि को मापने, स्कूल और जिले के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और जवाबदेही संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए किया जाता है। छात्र आकलन के अलावा, कई राज्यों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक मूल्यांकन प्रणालियां लागू की गई हैं, जो शिक्षक प्रदर्शन को छात्र उपलब्धि डेटा, कक्षा अवलोकन और अन्य मेट्रिक्स से जोड़ती हैं (स्टीनबर्ग और डोनाल्डसन, 2016)। शैक्षिक शासन में जवाबदेही प्रणालियों में स्कूलों और जिलों के लिए हस्तक्षेप, प्रतिबंध या पुरस्कार के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रदर्शन डेटा का उपयोग शामिल होता है।

इन प्रणालियों का लक्ष्य निरंतर सुधार को बढ़ावा देना, शैक्षिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना

और शासन के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना है।

6. संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक शासन में चुनौतियां और विवाद

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक शासन कई चुनौतियों और विवादों का सामना करता है जो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, समानता और प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

A. समानता और पहुंच के मुद्दे: उपलब्धि अंतराल, धन असमानताएं और संसाधन आवंटन

हाशिए के समुदायों के छात्रों को अक्सर संसाधनों तक असमान पहुंच, धन में असमानता और अपर्याप्त सहायता सेवाओं का सामना करना पड़ता है, जो शैक्षणिक उपलब्धि में असमानता को बढ़ा देता है (लैडसन-बिलिंग्स, 2006)। इन समानता और पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप, समान वित्त पोषण तंत्र और वंचित छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की आवश्यकता है (लुबिन्स्की और वीटज़ेल, 2010)।

B. जवाबदेही और मूल्यांकन: मानकीकृत परीक्षण, स्कूल प्रदर्शन मेट्रिक्स और जवाबदेही उपाय

मानकीकृत परीक्षण और स्कूल प्रदर्शन मेट्रिक्स पर जोर देने से उनकी प्रभावशीलता और शिक्षण और सीखने पर उनके प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है (पोफाम, 2005)। आलोचकों का तर्क है कि परीक्षण परीक्षा पाठ्यक्रम को सीमित कर देता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह निर्णय लेने और सुधार के प्रयासों के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है (निकोल्स और बर्लिनर, 2007)। शैक्षिक शासन में जवाबदेही की आवश्यकता को सार्थक मूल्यांकन प्रथाओं के साथ संतुलित करना एक चुनौती बनी हुई है (डार्लिंग-हैमंड, 2000)।

C. निजीकरण और बाजारीकरण: चार्टर स्कूल, वाउचर कार्यक्रम और स्कूल पसंद नीतियां

चार्टर स्कूलों, वाउचर कार्यक्रमों और स्कूल विकल्प नीतियों के उदय ने शैक्षिक परिदृश्य को नया रूप दिया है, जिससे सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में बाजार-आधारित प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है (चब्ब और मोए, 1990)। जबकि समर्थकों का तर्क है कि ये पहल नवाचार और माता-पिता की पसंद को बढ़ावा देती हैं, आलोचक समानता, जवाबदेही और निजीकृत संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं (रविच, 2013)। शिक्षा के निजीकरण ने शिक्षा में सरकार की भूमिका और पब्लिक स्कूलिंग के भविष्य पर बहस छेड़ दी है (लाबरी, 2012)।

D. राजनीतिक ध्रुवीकरण और शैक्षिक नीति पर दलगत प्रभाव

राजनीतिक ध्रुवीकरण और दलगत प्रभावों ने शैक्षिक शासन में आम सहमति-आधारित समाधान विकसित करने और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को बाधित कर दिया है (हेनिग और रिच, 2011)। स्कूल फंडिंग, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षा सुधार रणनीतियों जैसे मुद्दों पर वैचारिक विभाजन ने नीतिगत अस्थिरता और असंगतता को जन्म दिया है (डिमार्टिनो और क्लार्क, 2013)।

7. शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार और श्रेष्ठ अभ्यास

A. सहयोगी प्रबंधन और निर्णय निर्माण के लिए वादामय दृष्टिकोण

शिक्षा प्रणालियों द्वारा सामने आने वाली जटिल चुनौतियों को समाधान के रूप में सहयोगी प्रबंधन को ज़्यादा ध्यान मिला है। इस क्षेत्र में कई अच्छे दृष्टिकोण प्रकट हुए हैं:

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 4, Issue 2, Mar.-Apr., 2024, pp: 897-905 www.ijhssm.org

समुदाय-आधारित निर्णय निर्माण परिषद: इन परिषदों में विभिन्न हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों, जैसे माता-पिता, शिक्षक, प्रशासक, और समुदाय के सदस्य, को व्यक्तिगत स्कूल या जिलों के निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। यह दृष्टिकोण स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने, स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने, और विशेष समुदाय की आवश्यकताओं पर निर्देशित समाधान प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

हितधारक सलाहकार परिषद: शिक्षा एजेंसियों और नीति-निर्माताओं को विभिन्न पृष्ठभूमियों से हितधारकों को एकत्र करने के लिए सलाहकार परिषद स्थापित किया जा सकता है, जैसे शिक्षाविद, शोधकर्ता, व्यावसायिक नेता, और प्रचारक समूह (ब्रेवर इत एल., 2014)। ये परिषद विविध परिपेक्ष्यों को प्रदान करते हैं, निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को सूचित करते हैं, और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं।

सार्वजनिक-निजी साझेदारिता: सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों और निजी संस्थाओं, जैसे कि गैर-लाभकारी संगठन, व्यावसायिक संगठन, और धर्मयान फाउंडेशन्स, के बीच सहयोग संबंधों से संसाधित संसाधन, विशेषज्ञता, और नवाचारी समाधानों का लाभ उठा सकता है (डोनाह्यू और जेकहाउज़र, 2011)। ये साझेदारिता पाठ्यक्रम विकास से लेकर शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास तक की पहुंच में सहायक हो सकती हैं।

B. सफल प्रबंधन मॉडल और सुधारों के उदाहरण

कई राज्य और जिले ने सफलतापूर्वक प्रयोग किए हुए प्रबंधन मॉडल और सुधार लागू किए हैं जिन्होंने अच्छे परिणाम प्रदर्शित किए हैं:

पोर्टफोलियो स्कूल जिला मॉडल: नई ऑरलिंस और डेन्वर जैसे शहरों में प्रारंभ किया गया यह मॉडल, एक पोर्टफोलियो के भीतर स्कूलों के अधिक स्वायत्त सिस्टम में जिसमें सेंट्रल जिला कार्यालय प्रदर्शन मानकों को सेट करता है, समर्थन प्रदान करता है, और जवाबदेही सुनिश्चित करता है (बल्कली इत एल., 2020)।

समुदाय स्कूल: समुदाय स्कूल मॉडल का उद्देश्य स्कूलों को छात्रों, परिवारों, और बड़े समुदाय के लिए सम्पूर्ण सेवाओं और समर्थन के हब्स में परिवर्तित करना है (ओक्स इत एल., 2017)।

वजनित छात्र फंडिंग: कुछ जिले, जैसे कि बोस्टन और ह्यूस्टन, व्यक्तिगत छात्र की आवश्यकताओं पर आधारित संसाधन को आवंटित करने के लिए वजनित छात्र फंडिंग सूत्र अपनाया है (बेकर, 2016)।

C. शैक्षिक प्रबंधन अनुसंधान और अभ्यास में आगंतुक रुझान

शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र के विकास के साथ, कई उभरते रुझान और ध्यान के क्षेत्र अनुसंधान और अभ्यास को आकार दे रहे हैं:

डेटा द्वारा निर्णय निर्माण: शैक्षिक डेटा और उन्नत विश्लेषण उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता ने निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में डेटा द्वारा निर्धारित निर्णय निर्माण पर जोर दिया है।

समानता और सामाजिक न्याय: समानता, समावेशन, और सामाजिक न्याय के मुद्दे शैक्षिक प्रबंधन अनुसंधान और अभ्यास के केंद्र में आ गए हैं।

प्रौद्योगिकी एकीकरण: शैक्षिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने प्रभावी निर्णय निर्माण के लिए प्रणालियों, नीतियों, और सहायता प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता को उत्पन्न किया है।

8. निष्कर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रबंधन का अध्ययन एक जटिल और बहुपहलू प्रणाली का खुलासा करता है, जो ऐतिहासिक विकासों, सामाजिक

राजनीतिक बलों, और स्थायी चुनौतियों को समाधान करने के लिए लगातार प्रयासों के परिणाम से आकार पाता है। संघीय, राज्य, और स्थानीय अधिकारियों के बीच जटिल खेल, साथ ही विभिन्न हितधारकों का विविध समूह, एक गतिशील और लगातार विकसित दृश्य बनाता है।

मानकीकरण उपायों के बारे में बहसें, जैसे कि मानक परीक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन, डेटा द्वारा निर्णय निर्माण की आवश्यकता और निर्णय निर्माण में तंग पाठ्यक्रम और परीक्षण के लिए चिंताओं को हाइलाइट करती है। निजीकरण और स्कूल चयन की पहुंच और बढ़ाती

इन चुनौतियों के बावजूद, इस लेख में वाद-विवाद में अच्छी नई और उत्तम प्रथाओं को हाइलाइट किया गया है जो संभावित समाधान प्रदान करते हैं। सहयोगी प्रबंधन दृष्टिकोण, जो हितधारक सहभागिता और साझेदारिता को बढ़ावा देते हैं, जटिल शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उम्मीद दिखाते हैं। समुदाय स्कूल और वजनित छात्र अनुदान जैसे सफल मॉडल इकाई न्याय को प्रमोट करने की क्षमता और व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

जैसे ही शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र आगे बढ़ता है, डेटा-द्वारा निर्णय निर्माण, समानता और सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत शिक्षा, और प्रौद्योगिकी एकीकरण जैसे उभरते चरणों और ध्यान केंद्र की दिशा में शैक्षिक प्रबंधन अनुसंधान और अभ्यास को आकार देगा। अंततः, समान और प्रभावी शैक्षिक प्रणाली का अनुसरण करने के लिए एक आत्मसमर्पितता, विविध हितधारकों के बीच सहयोग, और शैक्षिक उत्कृष्टता और संधान के मौलिक सिद्धांतों के प्रति अनवरत समर्पण की आवश्यकता है।

REFERENCES:

[1]. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
[2]. Baker, B. D. (2016). Exploring the consequences of charter school expansion in U.S. cities. Economic Policy Institute. https://www.epi.org/publication/exploring-the-consequences-of-charter-school-expansion-in-u-s-cities/
[3]. Barnett, W. S., & Masse, L. N. (2007). Comparative benefit-cost analysis of the Abecedarian program and its policy implications. Economics of Education Review, 26(1), 113-125. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2005.10.007
[4]. Brewer, T. J., Gritz, R. M., & Kim, J. S. (2014). Navigating the policy landscape: Engaging stakeholders in state education governance. In M. S. Tucker (Ed.), Governance in Education (pp. 81-94). Harvard Education Press.
[5]. Brunch, J. (2014). Governing public comment: The public comment process and its discontents. Regent University Law Review, 27, 1-49.
[6]. Bulkley, K. E., Henrick, E. C., & Lemons, R. W. (2020). Portfolio management models and student achievement: A comprehensive synthesis. Educational Policy, 34(3), 512-546. https://doi.org/10.1177/0895904818807321
[7]. Conley, D. T. (2014). Getting ready for college, careers, and the Common Core: What every educator needs to know. John Wiley & Sons.
[8]. Dee, T. S., & Jacob, B. A. (2011). The impact of No Child Left Behind on student achievement. Journal of Policy Analysis and Management, 30(3), 418-446. https://doi.org/10.1002/pam.20586
[9]. Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. Princeton University Press.
[10]. Engel, M. (2013). Situating community voice in educational governance: A case study of Chicago. In R. M. Hendricks (Ed.), Voices of Community (pp. 81-102). SUNY Press.
[11]. Figlio, D., & Loeb, S. (2011). School accountability. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), Handbook of the Economics of Education (Vol. 3, pp. 383-

423). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00008-9

[12]. Jennings, J. F. (2015). Presidents, Congress, and the public schools: The politics of education reform. Harvard Education Press.

[13]. Kaestle, C. F. (1983). Pillars of the republic: Common schools and American society, 1780-1860. Hill and Wang.

[14]. Khalifa, M. A., Gooden, M. A., & Davis, J. E. (2016). Culturally responsive school leadership: A synthesis of the literature. Review of Educational Research, 86(4), 1272-1311. https://doi.org/10.3102/0034654316630383

[15]. Lubienski, C. (2005). Public schools in marketized environments: Shifting incentives and unintended consequences of competition-based educational reforms. Phi Delta Kappan, 87(4), 277-283. https://doi.org/10.1177/003172170508700407

[16]. Manna, P. (2006). Control, persuasion, and educational accountability: Implementing the No Child Left Behind Act. Educational Policy, 20(3), 471-494. https://doi.org/10.1177/0895904805284050

[17]. Marsh, J. A., Farrell, C. C., & Berliner, B. (2016). Data-driven decision making in practice: A study of how principals use data in different contexts. Educational Management Administration & Leadership, 44(5), 791-810. https://doi.org/10.1177/1741143215587302

[18]. McGuinn, P. (2016). From No Child Left Behind to the Every Student Succeeds Act: Federalism and the education legacy of the Obama administration. Publius: The Journal of Federalism, 46(3), 392-415. https://doi.org/10.1093/publius/pjw014

[19]. McDonnell, L. M. (2005). No Child Left Behind and the federal role in education: Evolution or revolution? Peabody Journal of Education, 80(2), 19-38. https://doi.org/10.1207/S15327930pje8002_2

[20]. Mondale, S., & Patton, S. B. (2001). School, the story of American public education. Beacon Press.

[21]. Oakes, J., Maier, A., & Daniel, J. (2017). Community schools: An evidence-based strategy for equitable school improvement. Learning Policy Institute. https://learningpolicyinstitute.org/product/community-schools-equitable-improvement-brief

[22]. Patterson, J. T. (2001). Brown v. Board of Education: A civil rights milestone and its troubled legacy. Oxford University Press.

[23]. Polikoff, M. S., McEachin, A. J., Wrabel, S. L., & Duque, M. (2014). The waive of the future? School accountability in the waiver era. Educational Researcher, 43(1), 45-54. https://doi.org/10.3102/0013189X13518072

[24]. Steiner, L. (2017). Personalizing the path to success: Lessons for policy from pioneering competency-based education. Harvard Education Press.

[25]. Steinberg, M. P., & Donaldson, M. L. (2016). The new educational accountability: Understanding the landscape of teacher evaluation in the last decade. Education Finance and Policy, 11(3), 340-359. https://doi.org/10.1162/EDFP_a_00186

[26]. Verger, A., Lubienski, C., & Steiner-Khamsi, G. (Eds.). (2016). World yearbook of education 2016: The global education industry. Routledge.

[27]. Verstegen, D. A. (2015). On doing an analysis of equity and closing the opportunity gap. Education Policy Analysis Archives, 23(41), 1-18. https://doi.org/10.14507/epaa.v23.1809

[28]. Vigdor, J. L., Wong, M. D., Laird, J., Duncan, G. J., & Brice, J. (2020). The role of technology in improving education: Perspectives from innovation leaders. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/research/the-role-of-technology-in-improving-education/

[29]. Wong, K. K. (2008). Federalism, equity, and accountability in education. In B. S. Cooper, J. G. Cibulka, & L. D. Fusarelli (Eds.), Handbook of education politics and policy (pp. 19-29). Routledge.

[30]. Yell, M. L. (2016). The law and special education (4th ed.). Pearson.